

News Broadcasting & Digital Standards Authority
Order No. 118 (2021)

Order of NBDISA (formerly known as NBSA) on complaint dated 11.3.2021 received from Mr. Matin Rafiuddin Mujawar against Zee News regarding a programme aired on 8.3.2021 with respect to burqa ban in Switzerland

Complaint dated 11.3.2021:

The complaint relates to a news programme titled “*Taal Thok ke (Special Edition) Live: छिपे चेहरे के पीछे आतंक? | TTK Live | Burqa Ban Switzerland*” which was broadcast on 8.3.2021 on Zee News.

Zee न्यूज़ ने स्विज़रलैंड में लगने जा रहे बुर्के के पाबंदी को लेकर "इस्लाम और मुस्लिम समाज पर निशाना थाम है" बुर्के के विषय को चर्चे का मुद्दा बनाकर भारतीय मुस्लिम समाज की प्रतिमा का सीधे हनन किया है. Zee न्यूज़ लगातार प्रसार माध्यम का दुरुपयोग करके इस्लाम विरोधी अजेंडा चला रहा है.

Zee न्यूज़ बुरका पहन कर गुजरने वाली महिलाओं के पुरानी तस्वीरें दिखते हुए हेडलाइंस में बताता है "क्या भारत में भी लगेगी रोख ???" इस तरह जन समुदाय को अल्पसंख्यकों प्रति बरगलाने का प्रयास किया है. Zee न्यूज़ ने देश में रहने वाले मुस्लिम समाज के भावना दुखाना तथा फंडामेंटल अधिकारों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है.

इन खबरों में Zee न्यूज़ ने BJP और VHP संघटन से जुड़े निम्नलिखित पैनलिस्ट को डिबेट्स में आमंत्रित कर के मुस्लिम धार्मिक आस्था से जुड़े विषयों पर उल्ट सुलट सवालों और बहस (डिबेट्स) करवाकर इस्लाम के प्रतिमा को चोट पहुंचाई है.

Zee न्यूज़ ने सरेआम "छिपे चेहरे के पीछे आतंकी" इस हेडलाइंस द्वारा मुसलमानों को निशाना बनाया है. इस तरह मुस्लिम समुदाय को दहशद गार्द, आतंकवादी, एक्सट्रिमिस्ट, जेहादी कह कर कानून के कटघरे में खड़ा करने का षड़यंत्र रचा है.

अदिति त्यागी का कहना है : ये नकाब या बुरखे पर लगा हुआ बैन हो ऐसा नहीं है. यूरोप में एक के बाद एक से बड़े देश इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ फैसले ले रहे हैं. चेहरा ढकने पर पाबंदी की असली वजह आतंकी हमले की आशंका है. इन तस्वीरों को देखिये जरा. भारत में भी आप ने ऐसी तस्वीरें देखि होंगी जहा चेहरा ढककर पत्थरबाजी की जाती है तो कभी CAA के खिलाफ नकाब पोश लोग आप को दिखाई देते हैं. इन सब का मतलब होता है हिंसा फैलाना आतंक फैलाना।

कपिल मिश्रा का सम्प्रदायिक और मुस्लिम विरोधी भाषण CAA दंगे के लिए जिम्मेदार है. इस भाषण का प्रसार Zee न्यूज़ द्वारा किया गया था उसके बाद लोगों में हिंसा भड़क उठी.

Zee न्यूज़ और अधिकतर चैनल CAA के विरोध से दुखी हो चुके थे इस का बदला उन्होंने तब्लीग जमात पर corona के फैलाने के इल्जाम को लेकर भी किया था ऐसा मुंबई उच्च न्यायालय औरंगाबाद बेंच ने अपने जजमेंट में कहा है.

अदिति त्यागी : नकाब बैन करने के बहाने इस्लामिक कट्टरता पर चोट की गई है. यूरोप का बड़ा प्रहार इसे कहा जा रहा है. और अगर भारत इस तरह के वार के लिए तैयार है और अगर है तो फिर कितना तैयार है कब तैयार है और कैसे तैयार है.

निगत अब्बास : जब आप पड़दे को लेकर आते है तो कही न कही डोमिनान्स को बढ़ावा देते है और आप उसके हवाले से बात करते है,

निगत अब्बास के इन वाक्यों ने मुस्लिम समाज के विरुद्ध में गलत और क्रूर ऐसा सन्देश लोगो में परोचाया (इस बिच पुरे खबरों के दौरान हिंसक वीडियो के फ़ाइल चित्र दिखाकर मुसलमानो पर निशाना थमा जा रहा था.)

आदित्य त्यागी : पूरी दुनिया में इस वक्त जब फेस कवर करने पर बैन की बात की जाती है पब्लिक प्लेसेस में उसका सीधा सा मतलब लोग निकाल लेते है के ये तो बुरखा बैन है। ये जो दुनिया जिस तारीखे से खबरों को इंटरप्रेट करती है वो क्या दिखता है. क्या वो दिखता है के ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है इस वक्त डेमोक्रेसी वर्सेस अनाकी में. अनाकी इन थे सेन्स क्या हम ने जो देखा, लोगो ने अपने चेहरे छिपकर, यहाँ पर मैं यूरोप के कॉन्टेक्ट में बात कर रही हूँ. क्या हम उसका नतीजा देख रहे है जो के स्विज़रलैंड ने अपने रेफरेंडम में वोट किया है.

जिस तरह से बिकिनी पहनना शूज पहनना महिला का अधिकार है उसी तरह बुरखा पहना खुद को कवर करना महिला का अधिकार है. यही हमारी भारतीय संस्कृति में कभी भी किसी मर्द को चुनने को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता। लेकिन ये जानना जरूरी है के ये डिबेट ना ही इस्लाम के खिलाफ है, न मुसलमान के खिलाफ है ना मुसलमान महिला अधिकार के खिलाफ है. ये डिबेट हम कर रहे है उस कट्टर पंक्त मानसिकता की जो गलत होने के बावजूद भी झुकने को तैयार नहीं होजाता या विक्रिम कार्ड खेल के या अपराधियों की तरह अपराधी होकर अपने गलत बात करके अड़ने की बात करता है.

एक भी वर्से कुरान के दिखे जहाँ पे बुरखा पहचान ना इस्लाम में सबसे वाजिब बताया गया हो. इस तरह फिर फिर मजहबी बहस को अंजाम देते हुए आरती सिंह ठाकुर : इस्लामिक रेडिकललाइजेशन का रूप इस्लामिक टेरर में बदला इस्लामिक टेरर वॉर्ल्ड वाइड फिनोमेना बना. इस्लामिक रेडिकललाइजेशन है क्या ? इस के विक्रिम कौन है ? ये इस्लामिक एक्सट्रिमिज्म की लड़ाई है इस्लाम को जो पुलिटीटाइज्म है ये उसकी लड़ाई है

इस्लाम की वजह से कश्मीर में १९८९ में इस्लामिक टेरॉरिज्म शुरू हुआ उन्होंने टारगेट किसको बनाया? कश्मीरी वीमेंस को, के आप हिजाब पहनिए, आप बुरखा पहनिए, नहीं पहनेंगे तो आप पर अटैक्स होंगे, एसिड अटैक्स होंगे, लड़कियों का जींस पहनना बंद हुआ १९८९-९० में।

नकाब/ हिजाब ये फोरसेबले इम्पोज़िशन लगाया है इस्लामिक टेररिज्म ने फ्रांस इस पर लेजिस्लेशन ला चूका है इण्डिया में भी डेबिट हो रहा है के क्या बुरखा वाकई औरतो की चॉइस है ? ये अपने मर्जी से बुरखा पहनती है... ? कही ये तो नहीं के मुल्ला और मौलवी उनपे फ़ोर्स कर रहे है ??? क्या ये वाकई कुरान में लिखा है के उनको पहनना जरूरी है ? बुरखा किस कॉन्टेक्ट में आया और किस कॉन्टेक्ट में रिलेवेंट था ये देखना पड़ेगा

आरती सिंह जैसे पैनलिस्ट दवरा इस्लाम विषय पर गलत सलत चर्चा करवाकर Zee न्यूज द्वारा मुस्लिम विरोधी अभियान चलाया जा रहा है. Zee न्यूज समाचार माध्यम का गलत इस्तेमाल करके एक धर्म विशेष के बुरखे जैसे विषय को लेकर, जो की वो पहने या ना पहने ये उनके वैयक्तिक सवतंत्रता का अधिकार है ऐसे खबरों को पॉलिटाइज करके, देश में अल्पसंख्यकों के विरोध में हिंसक वातावरण लगातार निर्माण करने का प्रयास पिछले कई दिनों से कर रहा है.

Zee न्यूज इस तरह के कम्युनल एजेंडा से मेलमिलप से रहने वाले दो समाजो के बीच हर दिन हिंसक स्थिति निर्माण करने की साजिश कर रहा है जो साफ़ तौर से बिना किसी संदेह "छिपे चेहरे के पीछे आतंक? | TTKLive | Burqa Ban " इन खबरों को देखने के बाद स्पष्ट हो रहा है

ऐसे खबरों द्वारा Zee न्यूज़ एक लम्बे समय से मुस्लिम विरोधी प्रचार करके देश में इस्लाम और मुस्लिम अल्पसंख्याक समाज के प्रति घृणा, जनसमुदाय में रोष और एक हिंसक स्थिति निर्माण करने का एक लांब अभियान चला रहा है, ये एक गहरी साजिश है Zee न्यूज़ देश को भीषण हिंसा के स्थिति में झोकने का प्रयास कर रहा है. देश में तबाही, रक्त पात करने के लिए रचा हुआ एक षडयंत्र है. Zee न्यूज़ द्वारा प्रसार माध्यम के होने वाले दुरुपयोग के खिलाफ समय समय पर देश भर में तथा NBSA में कई संगीन शिकायते दर्ज है. ऐसे होते हुए भी इस तरह से द्वेष निर्माण करने वाली खबरों के प्रसार से Zee न्यूज़ ने कानून से बेखौफ़ होने की मिसाल पेश की है. हिंसा करने वाले अपराधी का कोई धर्म नहीं होता पर अगर Zee न्यूज़ को अगर देश में ऐसे खबरों से तबाही निर्माण करने से वक्त पर रेखा नहीं गया तो हिंसक स्थिति और तबाही फैलाने वाले का नाम Zee न्यूज़ है ये इतिहास में लिखा जाएगा...

Zee न्यूज़ की खबरे राष्ट्रीय एकात्मता और अखंडता के हित में घातक और नुकसान पहुंचानेवाली साबित हो रही है. Zee न्यूज़ देश को हिंसा के तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है. Zee न्यूज़ ने सांप्रदायिक इरादों से भारतीय मुस्लिम समाज तथा उनके मौलिक और मानवाधिकारों को लक्षित किया है. मुस्लिम समाज की मानहानि करके उसे निचा दिखाया है. Zee न्यूज़ प्रसार माध्यम भड़काऊ खबरों द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए खतरा निर्माण कर रहा है. देश के विरुद्ध युद्ध पुकारने के बराबर अपराध किया जा रहा है.

Complaint dated 24.3.2021 filed with NBSA:

The complainant stated that he was escalating his complaint to NBSA since he had not received a response from the broadcaster. That this happened many times which implied that the broadcaster has no fear of law and order and was not bothered about the legal consequences arising out of the broadcasting news that hurt the religious and fundamental rights of minority.

Response from the broadcaster:

The broadcaster in its reply dated 23.4.2021 stated that in the complaint various false, misleading, frivolous and motivated allegations have been raised against the content of the programme '*Taal Thok Ke*' aired on Zee News on 8.3.2021.

At the outset, the broadcaster stated that the present complaint was not maintainable inasmuch as the same had not been filed in consonance with the provisions of the NBSA Regulations, particularly Regulation 8.4 which required the complainant to give a declaration at the bottom of the complaint. Further, the complaint was not maintainable inasmuch as, the impugned programme did not violate any of the Guidelines and Code of Ethics framed by the News Broadcasters Association and the Hon'ble NBSA. The impugned programme was completely neutral, objective and impartial and as such, the present complaint was nothing but a malicious attempt on the part of the complainant to muzzle the voice of a responsible media from reporting the truthful account of important facts and events. The broadcaster stated that since the complaint was not in consonance with the News Broadcasting Standards Regulations it was liable to be dismissed. Further, the allegations levelled in the complaint were completely baseless, motivated and the

contents of the impugned programme were never intended to outrage the religious feelings of Muslim Community or disturb the communal harmony, as falsely alleged.

The broadcaster stated that as a responsible media house of the country, it has the utmost respect for the Constitution of India and its values and as such, treats all the religions, class, communities alike and it telecasts its news reports without any flavour of biasness and partiality.

In the impugned programme, it had reported and conducted a objective, neutral and fair panel discussion on the referendum conducted in Switzerland, where majority of people backed a ban on full face covering in public places. During the programme, it had conducted a discussion on the issues as to why a need was felt to put a ban on face veil and whether the other countries, should also consider taking such steps, to stop the terrorist related activities. It was also reported that the objective behind the aforesaid decision was to stop terrorist activities, inasmuch as, the people execute their criminal activities by covering their faces, so as to hide their identity. Therefore, it was reported that the decision was taken due to security concerns.

Further, the broadcaster stated that during the programme the anchor, clarified, on number of occasions that the issue involved pertained to ban on covering the face and not burqa or anything related to any particular religion. The anchor also categorically stated in the show that the aforesaid issue was also not related to the rights of Muslim Women. In the show it had fairly debated on the issue of taking steps to stop illegal and terror related activities of radicals and extremist people, which has no connection whatsoever with the Muslim Religion. Therefore, it is absolutely false to allege that the impugned programme targeted any minority group or created a religious tension. The programme was in due compliance of the journalistic norms, applicable code of conduct and the relevant guidelines issued by this Hon'ble Authority. It reiterated that the impugned programme was completely impartial, neutral, objective and fair and did not tend to hurt the religious sentiments of any particular religion or group.

Moreover, it was pertinent to note that the impugned programme was a live debate and not a pre-scripted programme. Furthermore, during the programme, it had repeatedly run a disclaimer on the screen, in a the form of a ticker, clearly stating that "*the views expressed by the panellists on the show are their personal views and Zee News has nothing to do with the views/ comments made by the panellist and the panellist will personally be liable for the comments made by them during the show.*" The Disclaimer further stated that "*Zee News do not intend to hurt the sentiments of anyone*". In view of the aforesaid disclaimer, it stated that the channel neither endorsed nor could be made liable for the statements/ comments made by any of the panellists.

The broadcaster denied that the impugned programme was aired with the intent to provoke the communal disharmony or religious tension. It reiterated that its reporting in the impugned broadcasts was completely uncolored from any motive, prejudice or notions and was based completely on verified, accurate and established facts and did not promote disharmony or enmity between the different religion. The broadcaster stated that it had exercised self-restraint while conducting the analysis in the impugned show.

Thus, in view of the aforesaid, it submitted that it had neither breached any of the Guidelines of NBSA nor committed any of the offences, much less the offences under various Sections of Indian Penal Code or under Section 19 and 20 of the Cable Television Network Regulation Act, as alleged.

In view of the above, the broadcaster stated that it had abided by the principles of news reporting, broadcasting and journalistic norms and since the complainant had failed to establish any deviations therefrom the complaint ought to be dismissed at the outset.

Rejoinder dated 2.5.2021 from the complainant:

The complainant stated that the news was communally framed. He reiterated that the contents of the programme appeared to be pre-planned agenda for targeting minorities. The broadcaster has intentionally intended to cause danger and harm to the life and democratic rights of minorities as well as disturb the communal harmony of the state. That the broadcaster was frequently targeting minority by airing such provocative news and was attempting to create communal unrest in the country which needed to be stopped with penalty and strict legal action and cancellation of the license to broadcast of news.

Hence the complainant stated that it had previously also filed few more complaints against the broadcaster to bring to the notice of NBSA well planned communal agenda of the broadcaster which was designed to target and cause harm to the rights of the minorities and cause damage to the National Integration.

The complainant requested for NBSA to personally look in the subject news to know and understand the level of thick skinned intentions of the broadcaster who was very smartly carrying out a well planned attack against Islam, Muslims and Minorities of the country through its series of news.

The broadcaster has labelled the Indian Muslims as terrorist by stating that it was the real picture behind their hidden faces. The broadcaster also targeted the Indian Muslims who protested against the CAA NRC and the panellists invited on the show are also influenced by the ideology of the broadcaster and have no space to target Islam.

The effects of broadcasting of such communally flavored news by the media houses across India has resulted in hate against Minorities, communalism, destruction of

property, incidents of rioting, vandalism, and arson during the protests across the country. Violence erupted during the protest of NRC and CAA is one of the example of the same. The complainant stated that the response submitted by the broadcaster was nothing but an attempt to escape from the clutches of the law.

Decision of NBSA on 28.5.2021

NBSA considered the complaint, response from the broadcaster, and reviewed the footage of the broadcast. NBSA was of the view that further hearing was necessary to determine whether the broadcaster had violated the Code of Ethics and Broadcasting Standards and the Specific Guidelines Covering Reportage. NBSA decided that the complainant and the broadcaster along with a senior member of the editorial team be called for a hearing.

On being served with notice, the following were present at the hearing on 24.9.2021:

Complainant:

Mr. Matin Rafiuddin Mujawar
Mr. Ashish Kachave, Advocate

Broadcaster:

Ms. Ritwika Nanda, Advocate
Mr. Piyush Choudhary, Compliance Officer, NBDSA & Senior Manager, Legal
Ms. Annie, Assistant Manager, Legal

Submissions of the Complainant:

The complainant submitted that the broadcaster had through the programme titled “*TaalThok ke (Special Edition) Live: छिपे चेहरे के पीछे आतंक? Burqa Ban Switzerland*” targeted the Muslim community. He stated that during the programme, the anchor used inflammatory language and misrepresented the burqa which is part of the Islamic dress code. Further, during the programme the following statements were made by the anchor juxtaposing the objective behind the ban on face coverings in Sweden with the situation in India.

“अदिति त्यागी : आप को ये समाज ना है के खबर सिर्फ इतनी नहीं है. ये नकाब या बुरखे पर लगा हुआ बैन हो ऐसा नहीं है. इस खबर के मायने कही और ज्यादा है. वो भी ये देखते हुए के यूरोप के ज्यादा तर देश आप ने बीते दिनों में देखा होगा। के फ्रांस में किस तरह इस्लामिक कट्टरता के खिलाफ कानून बनाया हॉ फिर यूरोप के कही देश एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले ले रहे है चेहरा ढकने पर पाबंदी की असली वजह आतंकी हमले की आशंका है.

इन तस्वीरों को भारत के संदर्भ में सोचे जरा, भारत में भी आप ने ऐसी तस्वीरें देखि होगी जहा चेहरा ढककर पत्थरबाजी की जाती है तो कभी CAA के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर नकाब पोश लोग आप को दिखाई देते है. इन सब का

मतलब होता है हिंसा फैलाना आतंक फैलाना इसी लिए ताल ठोक के इस स्पेशल एडिशन में स्विज़रलैंड के रिफ़रेंडम है लेकिन भारत के नजरिये से इस पर डिबेट करना ज़रूरी है. बड़ा सवाल यही है के छिपे चेरे के पीछे आतंक पनप रहा है. नकाब बैन करने के बहाने इस्लामिक कट्टरता पर चोट की गई है. यूरोप का बड़ा प्रहार इसे कहा जा रहा है. और अगर भारत इस तरह के वार के लिए तैयार है और अगर है तो फिर कितना तैयार है कब तैयार है और कैसे तैयार है”

The complainant asserted that the broadcaster habitually refers to incidents abroad to spread communalism in India. In the impugned programme, he submitted that women with their faces hidden under the burqa were shown and the debate was on burqa despite the broadcaster claims that the subject of the debate pertained only to ban on face covering and not burqa or anything related to any particular religion. Further, even the complete title of the programme mentioned Burqa Ban, therefore he asserted that the broadcasters claim that the debate was only on face covering was false.

Submissions of the Broadcaster:

The broadcaster submitted that the impugned programme was a panel discussion on the occasion of Women’s Day and had an all women panel comprising of panellists and that it was pertinent to note herein that three of panellists on the impugned programme were women practicing Islam.

It submitted that debate/panel discussion in the impugned programme was conducted in the context of the referendum conducted in Switzerland, where majority of people backed a ban on full face covering/face veil in public places. The broadcaster had clarified in the programme that the ban was not specifically on burqa/niqab but was on face veil and it was in the context of this ban which had resulted in worldwide discussions that the ban targets Muslim women that the impugned programme was conducted. The discussion was not intended to adjudge the correctness of the law passed by government of Switzerland.

The broadcaster stated that during the impugned programme, three questions were raised including “छिपे चेहरे के पीछे आतंक”, which the broadcaster clarified did not refer to Muslim women. Throughout the impugned programme, it submitted that various instances were shown of men with their face covered with handkerchief engaged in stone pelting and burning buildings in India as well as abroad. In fact one of the panellists also mentioned that an RSS supporter under a burqa had also incited violence. The broadcaster submitted that it is generally easier for men/women to commit crimes with their faces hidden.

It submitted that it was one of the panellist who stated that she believed that the ban targets Muslim women and who was immediately cut short by the anchor who clarified that Swiss Referendum was not related to burqa/niqab ban but a ban on face veil for security reasons. During the programme, the anchor further clarified that it was the panellist who was attempting to take the discussion in a completely

different direction and thereafter it was the other panellists who practiced Islam remarked on the rightness/wrongness of the burqa. It is pertinent to note herein that another panellist on the programme clarified that the ban was undertaken by Switzerland for national security reasons.

The broadcaster submitted that in the programme, the discussion was also on the question whether India would be able to implement similar step considering the backlash/opposition received by Switzerland in the interest of national security. The other panellists also mentioned instances where men with face veil had committed offenses and stated that national security was paramount. In view of the above submissions, the broadcaster reiterated that the panel discussion had taken place on face veil and not on burqa ban.

NBDSA questioned the broadcaster that if the discussion was in the context of face veil, then why was the panel majorly composed by women from Muslim community and why was the discussion held on Women's Day. Further, it stated that it seems like that in the programme only burqa and not other face veils like ghoonghat were mentioned. The broadcaster submitted that the Swiss Referendum was passed on 7.2.2021 and impugned programme was conducted next day on 8.2.2021 coincidentally on the occasion of Women's Day and therefore, it had an all women panel.

Decision

NBDSA looked into the complaint, response from the broadcaster, and also gave due consideration to the arguments of both the complainant and the broadcaster and reviewed the footage.

After considering the programme in its entirety, NBDSA rejected the broadcaster's argument that the programme was only on the issue of ban on face veil and not on burqa ban. NBDSA observed that while the debate started as a panel discussion on the Swiss Referendum which banned full face covering/veil in public places, however, the thrust of the debate was not on the ban of face veil but on burqa which was also clear from the title and from the visuals of burqa clad women shown during the programme.

NBDSA noted that in the programme, the panelists were selectively chosen to promote a particular narrative which narrative was not only communal but also lacked objectivity and impartiality.

NBDSA notices that the above programme violates the Specific Guidelines Covering Reportage dated 10.2.2009 relating to Racial & Religious Harmony, which states that "*Racial and religious stereotyping should be avoided*" and "*Caution should be exercised in reporting content which denigrates or is likely to offend the sensitivities of any racial or religious group or that may create religious intolerance or disharmony*". Accordingly, NBDSA expresses

its strong “disapproval” to the said programme and cautions the broadcaster not to repeat the aforementioned violations in future.

In view of the above, NBDSA, therefore, directed that the video of the said broadcast, if still available on the website of the channel, or YouTube, or any other links, should be removed immediately, and the same should be confirmed to NBDSA in writing within 7 days.

NBDSA decided to close the complaint with the above observations and inform the complainant and the broadcaster accordingly.

NBDSA directs NBDA to send:

- (a) A copy of this Order to the complainant and the broadcaster;
- (b) Circulate this Order to all Members, Editors & Legal Heads of NBDA;
- (c) Host this Order on its website and include it in its next Annual Report and
- (d) Release the Order to media.

It is clarified that any statement made by the parties in the proceedings before NBDSA while responding to the complaint and putting forth their view points, and any finding or observation by NBDSA in regard to the broadcasts, in its proceedings or in this Order, are only in the context of an examination as to whether there are any violations of any broadcasting standards and guidelines. They are not intended to be 'admissions' by the broadcaster, nor intended to be 'findings' by NBDSA in regard to any civil/criminal liability.

Sd/-

**Justice A.K Sikri (Retd.)
Chairperson**

Place: New Delhi

Date : 19.11.2021